

राजस्थान राज्य... अपीलार्थी

बनाम

गिरधारी लाल... प्रतिवादी

दंड संहिता, 1860 - एसएस.306 और 304बी - शादी के 7 साल के भीतर जलने के कारण विवाहित महिला की मृत्यु - मृतक पीडब्लू1 की बेटी थी, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-पति (प्रतिवादी) को आईपीसी की धारा 304बी के तहत दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। आजीवन कारावास - अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304बी से धारा 306 आईपीसी में बदल दिया और सजा को आजीवन कारावास से घटाकर पांच साल कारावास कर दिया - औचित्य - क्या पीडब्लू1 की बेटी की मौत दहेज हत्या का उदाहरण थी या उसे भगाया गया था प्रतिवादी द्वारा आत्महत्या करना - माना गया: इस बारे में कोई विशेष आरोप नहीं है कि क्या प्रतिवादी ने दहेज की मांग की थी - इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले, मृतिका को प्रतिवादी द्वारा या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। कोई भी, दहेज की मांग - ऐसे घटक के अभाव में, उपधारणा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रतिवादी ने दहेज के लिए हत्या की थी - हालाँकि, प्रत्यक्ष और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी द्वारा मृतिका के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया था - क्रूरता और उत्पीड़न के ऐसे व्यवहार के परिणामस्वरूप, उसे आत्मघाती व्यक्ति से मिलने के लिए प्रेरित किया गया था मृत्यु - अपीलीय न्यायालय (उच्च न्यायालय) ने मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही माना कि इस तरह के आत्मघाती कृत्य को प्रतिवादी ने उकसाया था और उसे आईपीसी की धारा 306 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - एसएस 113ए और 113बी के तहत दोषी ठहराया।

दंड संहिता, 1860 - धारा 304बी - के तहत अपराध - मुख्य घटक - धारित: इसके तहत अपराध का मुख्य घटक आईपीसी की धारा 304बी जो राज्य द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या "अपनी मृत्यु से ठीक पहले" मृतिका को उसके पति द्वारा "दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में" क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, ताकि "दहेज -" का आरोप लगाया जा सके। वह अवधि जो "जल्द ही पहले" शब्द के भीतर आ सकती है, वाई की मृत्यु बी को समय सीमा के चार कोनों के भीतर नहीं रखा जा सकता है - इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों के आधार पर इसके निर्धारण के लिए न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है - शब्द और वाक्यांश - शब्द " शीघ्र पहले" - का अर्थ। अ.सा.1 की बेटी की शादी प्रतिवादी से हुई थी। उसकी शादी के 7 साल के भीतर जलने से मृत्यु हो गई। आरोप है कि शादी के शुरुआती दिनों से ही ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतिका को प्रताड़ित किया जाता था।

ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा 304 बी आईपीसी से 306 आईपीसी में बदल दिया और सजा को आजीवन कारावास से घटाकर पांच साल ई कारावास कर दिया।

राज्य की त्वरित अपील में, विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या पीडब्लू.1 की बेटी की मृत्यु दहेज हत्या का उदाहरण थी या क्या उसे उसके पति (प्रतिवादी) द्वारा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए माना:

1. आईपीसी की धारा 304 बी के तहत अपराध का मुख्य घटक जो राज्य द्वारा स्थापित किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या "अपनी मृत्यु से ठीक पहले" मृतिका को उसके पति द्वारा "दहेज की मांग के लिए" क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। "दहेज मृत्यु" का आरोप लगाना। वह अवधि जो "अभी पहले" शब्द के अंतर्गत आ सकती है, उसे अंदर नहीं रखा जा सकता है

समय सीमा के चार कोने. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका निर्धारण न्यायालय पर छोड़ दिया गया है। [पैरा 8,11] [448-ई; 449-एच; 450-ए]

2. वर्तमान मामले में, मृतिका के पिता और माता (क्रमशः पीडब्लू.1 और पीडब्लू.7) ने दहेज की मांग के संबंध में अशुभ बयान दिया कि शादी के बाद, मृतिका के ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग की गई थी। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या प्रतिवादी ने दहेज की मांग की थी। [पैरा 11] [450-बी]

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी दहेज हत्या की धारणा से संबंधित है।

वर्तमान मामले में इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले, मृतिका को दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके पति, प्रतिवादी द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। ऐसे घटक के अभाव में यह धारणा नहीं बनाई जा सकती कि प्रतिवादी ने दहेज हत्या का कारण बना। इस प्रकार अभियोजन पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी का लाभ नहीं उठा सकता। [पैरा 12] [450-सी, एफ-जी]

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ए एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा से संबंधित है। मौजूदा मामले में, प्रत्यक्ष और दस्तावेजी सबूतों से यह स्थापित होता है कि मृतक के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया था। क्रूरता और उत्पीड़न के इस तरह के व्यवहार के परिणामस्वरूप, उसे आत्मघाती मौत का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया। उसने अपनी शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी। इसलिए, अपीलीय अदालत ने मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही माना कि इस तरह के आत्मघाती कृत्य को उसके प्रतिवादी पति ने उकसाया था और उसे आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। [पैरा 13] [450-जी; 451-डी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1186।

जयपुर खंडपीठ, जयपुर बी में राजस्थान के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.03.2007 से डी.बी. 2000 की आपराधिक अपील संख्या 472।

अपीलार्थी की ओर से अर्चना पाठक दवे, मिलिंद कुमार।

प्रतिवादी की ओर से सतेंदर सिंग गुलाटी, कमलदीप गुलाटी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति

यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ की खंडपीठ द्वारा पारित 14 मार्च, 2007 के फैसले और आदेश के खिलाफ राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी-गिरधारी लाल द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, सजा को संशोधित किया और उसे आईपीसी की धारा 304 बी के बजाय आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया। उक्त अपराध के लिए, डिवीजन बेंच ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 1000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, अन्यथा उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। चूंकि प्रतिवादी-गिरधारी लाल पहले ही छह साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा काट चुका है, इसलिए उच्च न्यायालय ने उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, यदि किसी अन्य मामले में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि:

सूचक-जुगल किशोर (पीडब्लू.1) - मृतक बबीता के पिता ने 11 अगस्त, 1998 को अपनी लिखित शिकायत में बताया कि उनकी बेटा-बबीता (मृतक) की शादी चार साल पहले प्रतिवादी-गिरधारी लाल से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बबीता को प्रताड़ित कर रहे थे। इससे पहले भी बबीता के ससुराल वालों ने उसे जलाने का प्रयास किया था और पड़ोसियों ने उसे बचाया था। बाद में ससुराल वालों ने उसके माता-पिता को आश्वासन दिया कि वे बबीता को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन 10 अगस्त 1998 को उसे जलाकर मार दिया गया।

3. उक्त शिकायत पर आईपीसी की धारा 304बी और 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। उचित समय पर, मामला सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झुंझुनू के पास आया। प्रतिवादी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304बी के तहत लगाए गए आरोप से इनकार कर दिया गया, जिसने मुकदमे का दावा किया था। अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में कुल मिलाकर 9 गवाहों से पूछताछ की गई। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने स्पष्टीकरण में। पीसी, प्रतिवादी ने निर्दोष होने का दावा किया। बचाव पक्ष के दो गवाहों से भी पूछताछ की गई। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना करने और पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 304बी के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपील पर, जैसा कि ऊपर देखा गया, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 304 बी के बजाय आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया और उसे डिफॉल्ट रूप से 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसे छह महीने का सश्रम कारावास और भुगतना होगा।

4. अपीलार्थी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतक बबीता की शादी के 7 साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और प्रतिवादी ने घटना के संबंध में मृतक के माता-पिता को सूचित नहीं किया। अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के बाद कि मृतक की शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, निर्दोष साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। इसके अलावा, राज्य के विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि जुगल किशोर (पीडब्लू.1), नंद लाल (पीडब्लू.4) और श्रीमती। बिमला (पीडब्लू.7) ने दहेज की मांग के संबंध में मृतक के ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न और यातना के संबंध में बयान दिए हैं, जिनकी पुष्टि अन्य गवाहों के बयान और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से हुई है। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304बी से धारा 306 परिवर्तित करते समय और सजा को आजीवन कारावास से घटाकर पांच वर्ष कारावास में परिवर्तित करते समय उपरोक्त तथ्यों की उचित सराहना नहीं की गई।

5. दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का समर्थन किया।

6. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अध्ययन किया है।

7. मुकदमे में पेश किए गए सबूतों की बात करें तो, हम देखते हैं कि बबीता की प्रतिवादी गिरधारी लाल के साथ शादी के 5 से 6 साल के भीतर जलने से मृत्यु हो गई, जिससे मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्र.पी-6) पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु अत्यधिक जलने के कारण हुई। इसलिए, निर्णय के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या बबीता की मृत्यु दहेज हत्या का उदाहरण है या क्या उसके पति ने उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था?

8. धारा 304बी के तहत अपराध का मुख्य घटक जो राज्य द्वारा स्थापित किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या "अपनी मृत्यु से ठीक पहले" बबीता को उसके पति द्वारा "दहेज की मांग

के लिए या उसके संबंध में" क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। "दहेज हत्या" का आरोप लगाना।

जुगल किशोर (पीडब्लू.1) स्वयं शिकायतकर्ता हैं और मृतक बबीता के पिता हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब 6 या 7 साल पहले गिरधारी लाल से हुई थी। उक्त बयान 12 जून, 2000 को दर्ज किया गया था और घटना 10 अगस्त, 1998 को हुई थी। ग्राम छावसारी, जहां बबीता की शादी हुई थी, के एक अन्य निवासी श्याम लाल महाजन ने अपने बयान में कहा कि बबीता की शादी संपन्न हुई थी। वर्ष 1992-93 में आरोपी गिरधारी लाल के साथ। ऐसा ही बयान 12 जून, 2000 को जगदीश प्रसाद (पीडब्लू.3) ने दिया था और उन्होंने कहा था कि बबीता की शादी लगभग 6 या 7 साल पहले आरोपी गिरधारी लाल के साथ हुई थी। अतः यह स्पष्ट है कि बबीता की मृत्यु उसकी शादी के 7 वर्ष के अन्दर ही हो गयी।

9. बबीता की मृत्यु जलने की चोटों के कारण हुई और इस प्रकार मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई। डॉ. जेपी बुगालिया (पीडब्लू.6) के बयान से यह तथ्य साबित हुआ कि मौत जलने से हुई थी। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त 1998 को वह झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने डॉ. पीएस साहू के साथ बबीता का पोस्टमॉर्टम किया, जिसे 10 अगस्त 1998 को दोपहर 1.50 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शाम 4.00 बजे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर जलने के घाव थे।

10. जहां तक उत्पीड़न और क्रूरता का सवाल है, राजेंद्र प्रसाद (पीडब्लू.8) ने कहा कि गिरधारी लाल दहेज के लिए उसे पीटते थे। जुगल किशोर (पीडब्लू.1) ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है कि दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की जा रही थी, यह कहते हुए कि गिरधारी लाल बबीता को उसकी शादी के बाद दहेज के लिए पीटता और परेशान करता था। एक बार उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। उन्होंने यह भी कहा कि गिरधारी लाल ने पहले उसे एक कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की और जब उसे इस घटना के बारे में पता चला, तो वह श्याम लाल, फूल चंद, राजेंद्र, जगदीश के साथ उसके ससुराल गया। नेकी राम और मन रूप ने गिरधारी लाल और उसके पिता से उसे जिंदा जलाने के अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि वे इस घटना को नहीं दोहराएंगे। मृतक की मां बिमला देवी (पीडब्लू.7) ने अपने बयान में कहा कि आरोपी गिरधारी लाल और बबीता घटना से एक महीने पहले अपने गांव छावसरी आए थे और एक घंटे

तक वहां रुके थे। उस समय जुगल किशोर घर पर मौजूद नहीं था और बबीता ने अपनी मां से कहा कि वह उसके पिता को उसके ससुराल भेज दे क्योंकि गिरधारी लाल उसे परेशान करता था। इस बयान से साफ पता चलता है कि मौत से ठीक पहले बबीता के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया जा रहा था।

11. अब सवाल यह उठता है कि क्या बबीता को उसके पति ने उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के सिलसिले में ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया था। वह अवधि जो "जल्द ही पहले" शब्द के अंतर्गत आ सकती है, उसे समय सीमा के चार कोनों में नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका निर्धारण न्यायालय पर छोड़ दिया गया है।

वर्तमान मामले में, जुगल किशोर (पीडब्लू.1) और बिमला देवी (पीडब्लू.7) ने दहेज की मांग के संबंध में अशुभ बयान दिया है कि शादी के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग की गई थी। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गिरधारी लाल ने दहेज की मांग की थी या नहीं।

12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 313बी जो दहेज हत्या की धारणा से सम्बंधित है। इस प्रकार है

13. धारा 113 बी दहेज हत्या के बारे में उपधारणा.-जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया है, या उसके संबंध में, दहेज की किसी भी मांग पर न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा304बी में है।

वर्तमान मामले में इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले, बबीता को दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके पति गिरधारी लाल द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। ऐसे घटक के अभाव में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि गिरधारी लाल ने दहेज हत्या का कारण बना। इस प्रकार अभियोजन पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा113 बी का लाभ नहीं उठा सकता।

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ए एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा से सम्बंधित है जो इस प्रकार है: 113ए एक विवाहित महिला द्वारा

आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में धारणा - जब सवाल यह है कि क्या एक महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था और यह दिखाया गया है कि उसने सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी उसकी शादी की तारीख से वर्षों बाद और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी, अदालत मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उकसाया था।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" का वही अर्थ होगा जो भारतीय पैनल कोड (1860 का 45) की धारा 498ए में है।

मौजूदा मामले में, प्रत्यक्ष और दस्तावेजी सबूतों से यह स्थापित होता है कि बबीता के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया था। क्रूरता और उत्पीड़न के ऐसे व्यवहार के परिणामस्वरूप उसे आत्मघाती मौत के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी। इसलिए, अपीलीय अदालत ने मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही माना कि इस तरह की आत्महत्या के लिए उसके पति गिरधारी लाल ने उकसाया था और उसे आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। अपील खारिज की जाती है।

(सुधांसु ज्योति मुखोपाध्याय)न्यायमूर्ति

(ए.के. सीकरी).....न्यायमूर्ति

परितोष शुक्ला (अधिवक्ता)